

शिव प्रसाद चुन्नीलाल जैन

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

फौजदारी अन्वीक्षा & अपराध किए जाने के समय, व्यक्ति का भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है & सामान्य उद्देश्य हेतु कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कृत्य धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता 1860 का सार।

जूरी द्वारा एक मुकदमे में अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 471 और सपठित 467 व धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के साथ आरोपी नंबर 1 के साथ संयुक्त रूप से आरोप लगाए गए। पहला आरोप यह था कि रेलवे प्रशासन को धोखा देने के उनके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी नंबर 1 ने धोखाधड़ी की थी या जाली रेलवे रसीद का बेईमानी से उपयोग किया। दूसरा वैकल्पिक में आरोप तय किया गया। सबसे पहले सभी आरोपियों पर धारा 467 सपठित 34 आई.पी.सी. पर आरोपी नंबर 1 के खाते में बिल का हिस्सा जाली है, यह चार्ज लगाया गया। वैकल्पिक रूप से आरोपी नंबर 1 पर धारा 467 सपठित 109 आई.पी.सी. के तहत आरोपी नंबर 1 को उकसाने के लिए उस अपराध के कमीशन के तहत आरोप लगाए गए और अपीलकर्ताओं पर इसी तरह चार्ज नंबर 3 से 6 तक विकल्प में बनाया गया। जूरी ने विभिन्न अपराध में सपठित धारा 34 आई.पी.सी. में सभी आरोपियों के खिलाफ दोषी करार

दिया। विकल्प के पांच आरोप के संबंध में जूरी का फैसला दर्ज नहीं किया गया तथा अभियुक्त संख्या 1 के विरुद्ध ठोस अपराधों के संबंध में आरोप और विभिन्न अपराधों मय 109 आई.पी.सी. के संबंध में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध नहीं दिया गया। सेशन जज ने फैसला स्वीकार कर लिया जूरी ने उन्हें विभिन्न अपराधों मय 34 आई.पी.सी. के लिए दोषी ठहराया उच्च न्यायालय में उनकी अपीलें भी विफल रहीं। विशेष अनुमति द्वारा अपील पर अपीलकर्ताओं ने मुख्य रूप से प्रतिवाद किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जूरी को धारा 34 आई.पी.सी. की आवश्यकताओं के संबंध में गलत निर्देश दिया। इसका आग्रह किया गया कि विभिन्न अपराध वास्तव में जब आरोपी नंबर 1 द्वारा किये गये थे, तब अपीलकर्ता उपस्थित नहीं थे। आरोपी नंबर 1 ने रेलवे की जाली रसीदें पेश कीं अपराध कार्य किया और माल की डिलीवरी ली आँर इसलिए भी यदि वे धोखाधड़ी के लिए आरोपी नंबर 1 के साथ जाली रसीद पेश करके बेइमानी से माल लेने के लिए सहमत हुए थे। आँर उन्होंने विभिन्न अपराधों के कमीशन को बढ़ावा दिया हो।

लेकिन उन्हें धारा 34 आई.पी.सी. सहायता से अपराध करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जिसके प्रावधान मामले की परिस्थितियों में लागू नहीं होता। एक आरोपी के खिलाफ 34 की धारा के प्रयोज्यता के लिए जरूरी है कि उस अभियुक्त ने वास्तव में, अपराध का कमीशन या तो कुछ ऐसा करके जो आपराधिक कृत्य का हिस्सा बनता है या कम से कम ऐसा

करके कुछ ऐसा जो यह संकेत दे कि वह इसमें भागीदार था उस समय उस आपराधिक कृत्य किया गया था, इसमें भाग लिया था

माना गया: वर्तमान मामले में, आरोपी नंबर 1 ने अकेले ही विभिन्न कार्य किए जो उन अपराधों का गठन करते थे जिनमें वह अपराधी ठहराया हुआ था। अपीलकर्ताओं ने उन कृत्यों के वास्तविक कमीशन में कोई भाग नहीं लिया। उन कृत्यों को करने से पहले उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए अपराध का कोई घटक नहीं बनता था। यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने आपराधिक कृत्य के कमीशन में भाग लिया था, जो उन विभिन्न अपराधों की श्रेणी में आता है। इसलिए यदि वे कृत्य आगे बढ़ाने के लिए किए गए थे तो धारा 34 आई.पी.सी. के आधार पर अकेले आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए कृत्यों के लिए भी, उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तीनों आरोपियों का एक जैसा इरादा था इसलिए विभिन्न अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया।

बरेन्द्र कुमार घोष बनाम द किंग एम्परर, (1929) एल.आर. 52 में एक। 40, श्री कांतैया रामय्या मुनिपल्ली बनाम बॉम्बे राज्य [1955] 1 एस.सी.आर. 1177 और जयकृष्णदास मनोहरदास देसाई वि. बम्बई राज्य [1960] 3 एस.सी.आर. 319, संदर्भित.

निर्णय

आपराधिक अपीलिय क्षेत्राधिकार: 1961 की आपराधिक अपील संख्या 150 और 185।

1961 की आपराधिक अपील संख्या 218 और 242 में क्रमशः पूर्व बॉम्बे उच्च न्यायालय के 19 जून] 1961 के फैसले और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील। अपीलकर्ता के लिए एस- मोहन कुमारमंगलम, आर-के- गर्ग और एम- के- राममूर्ति, (सीआर ए संख्या 150@61 में।

अपीलकर्ता के लिए बी-एम- मिस्त्री, रविंदर नारायण और जे-बी-दादाचंजी, 1961 के सीआर- ए- संख्या 185 में।

प्रतिवादी की ओर से बी-के-खन्ना, बी-आर-जी-के- अचार और आर-एच- डेबर @दोनों अपीलों में

26 फरवरी 1964 अदालत का फैसला रघुबर दयाल जे- द्वारा सुनाया गया, शिव प्रसाद चुन्नीलाल जैन, जो 1961 की आपराधिक अपील संख्या 150 में अपीलकर्ता थे और आरोपी संख्या 3 थे और प्यारेलाल ईश्वरदास कपूर, आपराधिक अपील संख्या 185 में अपीलकर्ता थे। 1961 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बॉम्बे के समक्ष सत्र परीक्षण में आरोपी नंबर 2 पर रखा गया था। उनके साथ एक तीसरा अभियुक्त, रामेश्वरनाथ बृजमोहन शुक्ला भी था, जो मुकदमे में अभियुक्त नंबर 1 था।

चूँकि दो अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न होती हैं, हम उनका निपटान एक ही निर्णय से करेंगे। अपीलकर्ताओं को क्रमशः आरोपी नंबर 3 और आरोपी नंबर 2 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाले तथ्य यह हैं कि रेलवे रसीद नंबर 597481 के तहत फरवरी 1959 की शुरुआत में गोबिंद गढ़ से रायपुरम तक बड़ी मात्रा में लोहे के एंगल भेजे गए थे, उन्हें ई-आर- नंबर 69667 वाले एक खुले वैगन में भेजा गया था। लेबल वैगन को इटारसी रेलवे स्टेशन पर बदल दिया गया और इसे एक लेबल के तहत वाडी बंदर की ओर मोड़ दिया गया, जिसमें दिखाया गया था कि लोहे के एंगल रेलवे रसीद संख्या 43352 दिनांक 6 फरवरी, 1959 के तहत बारां से 16 फरवरी, 1959 वाडी बंदर भेजे गए थे। यह वैगन वाडी बंदर पहुंचा। 17 फरवरी को इसे बाबूराव गावड़े, पी-डब्ल्यू- 1 और श्रीधर, पी-डब्ल्यू- 14 द्वारा अनलोड किया गया। 18 फरवरी को आरोपी नंबर 1 ने बिल की डिलीवरी शीट प्राप्त की और उस पर श्री दत्ता के नाम पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने रेलवे से लोहे के एंगल की डिलीवरी भी प्राप्त की और श्री दत्ता के नाम पर रेलवे डिलीवरी बुक पर हस्ताक्षर किए। रेलवे अधिकारियों ने जाली रसीद संख्या 43352 प्रस्तुत करने और 1500 रुपये के शुल्क के भुगतान पर इन्हें दिया।

फिर इन लोहे के एंगलों को सेवरी में नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में ले जाया गया और वहां संग्रहीत किया गया। पुस्तक में प्रविष्टियों

में आरोपी नंबर 3 के खाते में उनकी रसीद दिखाई गई और आरोपी नंबर 2 के खाते में प्राप्त होने वाले सामान का संकेत देने वाली एक और प्रविष्टि भी शामिल थी। बाद वाली प्रविष्टि एक चिट की प्राप्ति पर बनाई गई थी, प्रदर्श जेड 8, आरोपी नंबर 1 से यह कहते हुए कि माल आरोपी नंबर 2 के नाम पर दर्ज किया जाना चाहिए। 24 फरवरी, 1959 को आरोपी नंबर 2 ने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुख्य कार्यालय को संबोधित एक सामान पहुंचाने के आवेदन, एक्ज़िबिट पर हस्ताक्षर किए। आरोपी नंबर 1 ने 26 फरवरी और 3 मार्च, 1959 को उस कंपनी के गोदाम से माल प्राप्त किया।

गोबिंद गढ़ से भेजे गए लोहे के एंगल न मिलने के बारे में मूल खेप की शिकायत के कारण जांच हुई और अंततः तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया।

छह आरोप तय किये गये। पहला आरोप सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 471 और 467 सपठित 34 आई.पी.सी. के तहत दंडनीय अपराध के लिए था और कहा कि रेलवे प्रशासन को धोखा देने के अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में, आरोपी नंबर 1 ने धोखाधड़ी या बेईमानी से जाली रेलवे रसीद संख्या 43352 का इस्तेमाल किया था।

विकल्प में दूसरा आरोप तय किया गया, सबसे पहले इसने सभी आरोपियों पर धारा 471 और 467 सपठित 34 आई-पी-सी- के तहत अपराध का आरोप लगाया। आरोपी नंबर 1 के बिल के हिस्से में जालसाजी

करने के कारण। विकल्प में, आरोपी नंबर 1 पर धारा 467 आई.पी.सी. के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। और अन्य आरोपी नंबर 2 और 3 पर धारा 467 सपठित 109 आई.पी.सी. के तहत उस अपराध को अंजाम देने में आरोपी नंबर 1 को उकसाने के लिए आरोप लगाए गए।

आरोप संख्या 3 से 6 को वैकल्पिक रूप से समान रूप से तय किया गया था, यानी पहले उदाहरण में सभी तीन आरोपियों पर धारा 34 आई.पी.सी. के साथ पढ़े गए कुछ अपराधों का आरोप लगाया गया था। जबकि वैकल्पिक रूप से आरोपी नंबर 1 पर विशिष्ट अपराध का आरोप लगाया गया था और अन्य दो आरोपियों पर उस अपराध का आरोप सपठित 109 आई.पी.सी. लगाया गया था।

अभियुक्तों पर जूरी की सहायता से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बॉम्बे द्वारा मुकदमा चलाया गया। जूरी ने धारा 34 आई.पी.सी. के साथ पढ़े गए विभिन्न अपराधों के लिए सभी आरोपियों के खिलाफ दोषी होने का सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। आरोपी नंबर 1 के खिलाफ मूल अपराधों के संबंध में पांच वैकल्पिक आरोपों के संबंध में और आरोपी नंबर 2 और 3 के खिलाफ सपठित धारा 109 आई.पी.सी. विभिन्न अपराधों के संबंध में जूरी का फैसला दर्ज नहीं किया गया था। सत्र न्यायाधीश ने जूरी के फैसले को स्वीकार कर लिया और उन्हें धारा 34 आई.पी.सी. के साथ पढ़े जाने वाले विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में उनकी

अपीलें असफल रहीं और इसलिए आरोपी नंबर 2 और 3 ने इस न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

अपीलकर्ताओं के लिए मुख्य तर्क यह है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने धारा 34 आई.पी.सी. की आवश्यकताओं के संबंध में जूरी को गलत निर्देश दिया। तर्क यह है कि विभिन्न अपराध वास्तव में 18 फरवरी को आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए थे, जब उसने जाली रेलवे रसीद पेश की, अन्य आपराधिक कार्य किए और लोहे की डिलीवरी ली तब न तो आरोपी नंबर 2 और न ही आरोपी नंबर 3 मौजूद थे। और इसलिए भले ही वे जाली रसीद पेश करके बेईमानी से लोहे के एंगल प्राप्त करके रेलवे प्रशासन को धोखा देने के लिए आरोपी नंबर 1 के साथ सहमत हुए हों, हो सकता है कि उन्होंने विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए उकसाया हो, लेकिन धारा 34 आई.पी.सी. की सहायता से वे अपराध दोषी नहीं हो सकते। यह तर्क दिया गया है कि इसके प्रावधान मामले की परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। यह तर्क दिया गया है कि धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए एक अभियुक्त के विरुद्ध, यह आवश्यक है कि उस अभियुक्त ने वास्तव में अपराध के कमीशन में भाग लिया था या तो कुछ ऐसा करके जो आपराधिक कृत्य का हिस्सा बनता है या कम से कम कुछ ऐसा करके जो यह दर्शाता हो कि वह अपराध के कमीशन में भागीदार था। वह आपराधिक कृत्य जिस समय किया गया था। बरेंद्र कुमार घोष बनाम द किंग एम्परर



(1) और श्रीकांतैया रामय्या मुनिपल्ली बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे (2) के रूप में रिपोर्ट किए गए मामलों पर भरोसा किया गया है।

इस मामले में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जूरी से कहा था

"यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तीनों आरोपियों के मन में एक समान इरादा था और आरोपी नंबर 1 उस सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा था, तो सभी आरोपी आरोपी नंबर के खिलाफ साबित हुए अपराधों के लिए जवाबदेह होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के प्रावधानों के आधार पर, और यह अकेले कहने से आरोप का कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए, आपको पहले खुद विचार करना होगा कि आरोपी नंबर 1 के खिलाफ कौन से अपराध साबित हुए हैं। आप इसके बाद अपने आप से पूछें कि क्या यह साबित हो गया है (और इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है) कि तीनों आरोपियों के मन में एक समान इरादा था और आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए कृत्य उसी सामान्य को आगे बढ़ाने के लिए किए गए थे। यदि आपका जवाब "हां" है तो तीनों आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के

आधार पर आरोपी नंबर 1 के खिलाफ साबित हुए आरोपों के लिए दोषी होंगे।"

यह तर्क दिया गया है कि इस प्रकार मामले को जूरी के सामने रखकर विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गलती की क्योंकि उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आरोपी नंबर 2 और 3 उस समय बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे जब विभिन्न अपराध वास्तव में आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए थे। अपीलकर्ताओं द्वारा जिन दो मामलों पर भरोसा किया गया है- वे उनके तर्क का समर्थन करते हैं। श्रीकांतैया के मामले में तीन व्यक्तियों को धारा 409 सपठित धारा 34 आई-पी-सी- के तहत भंडार डिपो के प्रभारी सरकारी सेवकों के रूप में उन्हें सौंपे गए कुछ सामानों के आपराधिक विश्वास का उल्लंघन करने के लिए कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

(1)आइ-एल-आर- 52- पेज- 40

(2)एस-सी-आर- पेज नम्बर 1177

पुना के पास देहु रोड पर भंडार अवैध रूप से डिपो से बाहर चला गया था और एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया गया था जो उन्हें डिपो से प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं था। यह आरोप लगाया गया था कि उन अभियुक्तों ने उन संपत्तियों की सरकार को धोखा देने की साजिश रची थी और उस साजिश के अनुसरण में उन्होंने माल को दूसरे व्यक्ति को बेचने की व्यवस्था की थी। उस मामले में आरोपी नंबर 1 तब मौजूद नहीं था

जब माल लोड किया गया था और न ही वह तब मौजूद था जब उन्हें गेट से बाहर जाने की अनुमति दी गई थी, यानी कि जब अपराध किया गया था तब वह मौजूद नहीं था। बोस जे. ने कोर्ट का फैसला सुनाते हुए पेज नम्बर 1189 पर कहा।

"यदि वह उपस्थित नहीं था, तो उसे धारा 34 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि जूरी ने इस आशय का फैसला सुनाया होता तो उसे उकसाने के लिए दोषी ठहराया जा सकता था क्योंकि उकसाने के सबूत हैं और उकसाने का आरोप कानून में सही है। लेकिन जूरी ने आरोप के उकसावे वाले हिस्से को नजरअंदाज कर दिया और हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि उन्होंने सबूत के इस हिस्से पर विश्वास किया या नहीं।"

जूरी को आरोप में गलत दिशा और धारा 34 आई.पी.सी. की आवश्यकताओं पर विचार करने में, विद्वान न्यायाधीश ने पेज नम्बर 1188 पर कहा-

"गलत निर्देशन का सार जूरी को उनके निर्देश में निहित है कि भले ही एक व्यक्ति वास्तव में अपराध होने पर उपस्थित नहीं हो सकता और भले ही वह स्क्रीन के पीछे रहे उसे धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है,

बशर्ते कि ऐसा साबित कर दिया कि अपराध सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। यह गलत है, क्योंकि यह धारा का सार है कि व्यक्ति को अपराध के वास्तविक कमीशन पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए।"

श्रीकांतैया का मामला (1) व्यावहारिक रूप से वर्तमान मामले के समान है। दोनों आरोपी नंबर 2 और आरोपी- नंबर- 3 ने 18 फरवरी को रेलवे स्टेशन पर अपनी उपस्थिति से इनकार किया जब विभिन्न अपराध किए गए थे। किसी ने भी गवाही नहीं दी कि आरोपी नंबर 3 तब मौजूद था। हालाँकि आरोपी नंबर 2 की उपस्थिति बाबू राव गावड़े, पी-डब्ल्यू- 1 द्वारा बताई गई थी। (1)1955 1 एस-सी-आर- पेज नम्बर 1177

उन्होंने जांच के दौरान पुलिस के सामने अपने बयान में ऐसा नहीं कहा था और विद्वान सत्र न्यायाधीश का सारांश यह था कि उन परिस्थितियों में यह जूरी को विचार करना था कि अदालत में गवाह के बयान पर विश्वास करना है या नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि आरोपी नंबर 2 के खिलाफ इस आपराधिक लेनदेन से जुड़े अन्य सबूत भी थे, जूरी ने 18 फरवरी को रेलवे स्टेशन पर उसकी उपस्थिति पर विश्वास किया या नहीं।

जयकृष्णदास मनोहरदास देसाई बनाम बॉम्बे राज्य (1) में श्रीकांतैया का मामला (2) विचार के लिए आया और तथ्यों के आधार पर प्रतिष्ठित किया गया। उस मामले में दो आरोपी जो एक कंपनी के निदेशक थे, को धारा 409 सपठित धारा 34 आई.पी.सी. के तहत उन्हें आपूर्ति किए गए कुछ कपड़ों के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करने के लिए अपराध का दोषी ठहराया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों में से एक उस अवधि के दौरान उस कारखाने में काम नहीं कर रहा था जब माल हटाया जाना चाहिए था और इसलिए उसे धारा 34 आई.पी.सी. के प्रावधानों का सहारा लेकर माल के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था। 34 आई.पी.सी. शाह जे- ने कोर्ट का फैसला सुनाते हुए पेज नम्बर 326 पर कहा-

"लेकिन धारा 34 के तहत दायित्व का सार एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में पाया जाना है जो अपराधियों को सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक आपराधिक कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है और अपराधी की उपस्थिति को धारा के तहत उत्तरदायी बनाने की मांग की जाती है। "34" कानून के शब्दों में इसकी प्रयोज्यता की शर्तों में से एक नहीं है। एक अपराध करने के लिए एक सामान्य इरादा मन की बैठक और अपराध को आगे बढ़ाने

में अपराध के कमीशन में भागीदारी वह सामान्य इरादा धारा 34 आई.पी.सी. के आवेदन को आमंत्रित करता है।

लेकिन यह भागीदारी सभी मामलों में भौतिक उपस्थिति से ही हो यह जरूरी नहीं है। शारीरिक हिंसा से जुड़े अपराधों में आम तौर पर संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर उत्तरदायी बनाए जाने वाले अपराधियों की अपराध स्थल पर उपस्थिति आवश्यक हो सकती है, लेकिन अन्य अपराधों के संबंध में ऐसा मामला नहीं है जहां अपराध में विविध कार्य शामिल हैं जो अलग अलग समय और स्थानों पर किया गया हो सकता है (1) 1960, 3 एस-सी-आर- पेज नम्बर 319-

(2) 1955 1 एस-सी-आर- पेज नम्बर 1177-

श्री कांतैया के मामले (1) में सरकारी डिपो से सामान हटाकर हेराफेरी की गई और सामान हटाने के अवसर पर पहला आरोपी मौजूद नहीं था। इसलिए यह संदिग्ध था कि क्या उसने अपराध के कमीशन में भाग लिया था, और उन परिस्थितियों में इस न्यायालय ने माना कि पहले आरोपी की भागीदारी स्थापित नहीं हुई थी। श्री कांतैया के मामले (1) में टिप्पणियाँ जहाँ तक वे एस से संबंधित हैं। हमारे

निर्णय में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को, स्थापित तथ्यों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए और इसका उद्देश्य सार्वभौमिक अनुप्रयोग का सिद्धांत निर्धारित करना नहीं है।"

वर्तमान मामले में आरोपी नंबर 1 ने अकेले ही 18 फरवरी, 1959 को विभिन्न कृत्य किए, जो उन अपराधों का गठन करते थे जिनके लिए उसे दोषी ठहराया गया था। अभियुक्त संख्या 2 और 3 ने उन कृत्यों के वास्तविक कमीशन में कोई हिस्सा नहीं लिया। उन कृत्यों को करने से पहले उन्होंने जो कुछ भी किया होगा, वह आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए अपराधों का एक घटक नहीं था। यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने आपराधिक कृत्य के कमीशन में भाग लिया था जो उन विभिन्न अपराधों के बराबर था। इसलिए धारा 34 आई.पी.सी. के आधार पर उन्हें अकेले आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। भले ही वे कार्य तीनों आरोपियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हों। इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि अपीलकर्ताओं अर्थात् अभियुक्त संख्या 2 और 3 को धारा 34 आई.पी.सी. के साथ पढ़े गए विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराये जाने को अलग रखा जाना है।

सबसे पहले, हमने अपीलकर्ताओं के खिलाफ किए जा रहे उकसावे के वैकल्पिक अपराधों पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को नहीं सुना और जिसके संबंध में जूरी का फैसला सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज नहीं किया गया

था। हमने उन आरोपों के संबंध में मामले को आगे की कार्यवाही के लिए भेजना आवश्यक नहीं समझा और अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को आगे की सुनवाई देने के बाद मामले को अंततः निपटाने को प्राथमिकता दी। तदनुसार हमने उन्हें (1) 1955 1 एस-सीआर- 1177 विभिन्न अपराध आरोप संख्या 2 से 6 की विषय वस्तु में अभियुक्त संख्या 1 को उकसाने वाले अपीलकर्ताओं के आयोग से संबंधित आरोपों पर सुना और अब उस मामले से निपटेंगे।

हमें रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और हम केवल उन विभिन्न तथ्यों पर ध्यान देंगे जो सबूतों से स्थापित होते हैं या जिन्हें अभियुक्तों द्वारा स्वीकार किया जाता है। आरोपी नंबर 2 द्वारा आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए अपराधों को अंजाम देने के लिए उकसाने के सवाल पर संबंधित प्रासंगिक तथ्य हैं:

1- आरोपी नंबर 1 आरोपी नंबर 3 का नौकर है जिसकी दुकान पर आरोपी नंबर 2, जो दलाल है, बैठा है।

2- आरोपी नंबर 2 अलौह वस्तुओं का कारोबार करता है।

3- अभियुक्त क्रमांक 2 बाबूराम गावड़े, पी-डब्लू- 1 के साथ 17 फरवरी 1959 को सामान देखने के लिए गया।

4- गोदाम रजिस्टर में शिव प्रसाद, बिमल कुमार और प्यारे लाल, अभियुक्त नंबर 2 के खाते में प्राप्त होने वाले एंगल आयरन दिखाए गए थे।



5- आरोपी नंबर 2 ने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी को एंगल आयरन के संबंध में डिलीवरी ऑर्डर जारी करने के लिए एक्जिबिट के पत्र लिखा, ताकि वह उसकी डिलीवरी ले सके।

6- आरोपी नंबर 2 के पास नोट, एक्जिबिट जेड 7 था, जिसे उसने जांच के दौरान पुलिस को दिया था।

आरोपी नंबर 3 द्वारा अपराधों को कथित रूप से उकसाने पर असर डालने वाले प्रासंगिक तथ्य हैं:

1- आरोपी नंबर 1 आरोपी नंबर 3 का कर्मचारी है।

2- आरोपी नंबर 1 के कहने पर एंगल आयरन को नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के डिपो में संग्रहीत किया गया था।

3 गोदाम की किताबों में उनकी रसीद आरोपी नंबर 3 के खाते में दर्ज की गई, हालांकि खाते में आगे दिखाया गया कि उन्हें आरोपी नंबर 2 के खाते में प्राप्त किया गया था। यह आगे की प्रविष्टि आरोपी नंबर 1 से प्रदर्श जेड 8 की प्राप्ति पर की गई थी, जब अंतिम लॉट 18 फरवरी को गोदाम में वितरित किया गया था।

4- किसी अज्ञात व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसके नीचे की तारीख को छोड़कर प्रदर्श जेड 7 पर संपूर्ण लेखन, आरोपी नंबर 3 द्वारा लिखा गया था। वह दस्तावेज यह है कि

पियाराया लाल, सी-ओ मेसर्स शेओपरशाद बिमल कुमार, बॉम्बे

1- आरआर- क्रमांक 43351 दिनांक 4-2-59 अशोकनगर से कार्नेक ब्रिज।

2- आरआर- क्रमांक 43352, दिनांक 6-2-59 बारां से वादी बंदर।

मुझे उपरोक्त आरआर की सामग्री प्राप्त हो गई है जिसे मैंने क्लीयरेंस के लिए आपको सौंप दिया है। हस्ताक्षर यशवंत 24-2-1959

इन परिस्थितियों के अलावा, राज्य से यह आग्रह किया जाता है कि इटारसी रेलवे स्टेशन पर वैगन को उसके सही रास्ते से मोड़ने का प्रभाव यह दर्शाता है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के पास धन के साथ एक काफी बड़ा और प्रभावशाली संगठन होना चाहिए और इस तरह के मोड़ से ऐसा हो सकता है। कोई भी मोड़ केवल आरोपी नंबर 1 आरोपी नंबर 3 के सभी कर्मचारी, जो एक बड़ा व्यापारी है, के कहने पर नहीं हुआ है, लगभग एंगल आयरन की डिलीवरी लेने से पहले रेलवे अधिकारियों को शुल्क के रूप में 1500 रुपये का भुगतान किया गया था, आरोपी नंबर 1 उस भुगतान को करने की स्थिति में नहीं था। आगे यह आग्रह किया गया है कि आरोपी नंबर 1 ने राष्ट्रीय परिवहन कंपनी के साथ माल का भंडारण नहीं किया होगा जब तक कि भंडारण उसके मालिक, आरोपी नंबर 3 के खाते में न हो।

आरोपी नंबर 2 स्वीकार करता है कि वह 17 फरवरी को सामान देखने गया था। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने वस्तुओं में अपनी रुचि

खो दी क्योंकि वे लोहे के कोण थे और उनका व्यवसाय अलौह वस्तुओं में था। उन्होंने एक्जिबिट के, के अपने हस्ताक्षर के बारे में यह कहते हुए समझाया कि उन्होंने आरोपी नंबर 3 के कहने पर ऐसा किया था, जिसने उन्हें बताया था कि आरोपी नंबर 1 ने गलती से आरोपी नंबर 2 और आरोपी के नाम पर सामान जमा कर लिया था। नंबर 3 उसे दस्तावेज एक्जिबिट जेड 7 दिखा रहा है जिसे उसने अपने पास रखा था।

आरोपी नंबर 3 का कहना है कि उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उसने आरोपी नंबर 2 के कहने पर एक्जिबिट जेड- 7 लिखा, जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, वह खुद अंग्रेजी या हिंदी में लिखने में असमर्थ था।

अब हम यह निर्धारित करने के लिए सबूतों पर चर्चा करते हैं कि क्या आरोपी नंबर 2 और 3 ने आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए अपराधों को अंजाम देने के लिए उकसाया था।

प्रदर्श जेड 7,जैसा कि मूल रूप से लिखा गया था, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पहली पंक्ति में पियाराया लाल सीओ लिखा हुआ है। ये बाद में लिखा गया यह स्पष्ट है, जैसा कि आरोपी नंबर 2 के लिए आग्रह किया गया था, कि इन तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक अलग कलम से लिखा गया है और संभवतः अलग स्याही से भी, और क्योंकि 'सीओ' शब्द एक असामान्य तरीके से लिखा गया है। सामान्य लेखन में, इसे बाद

की अभिव्यक्ति "मैसर्स" के अनुरूप होना चाहिए था। शेओपरशाद बिमल कुमार यह इस प्रकार है। इसलिए यह दस्तावेज़ सबसे पहले आरोपी नंबर 3 द्वारा यह दिखाने के लिए लिखा गया था कि किसी तीसरे व्यक्ति ने उसे रेलवे रसीद नंबर 43352 सौंपा था और दिनांक 6 फरवरी 1959 को और उस व्यक्ति को वह सामग्री प्राप्त हुई थी जिससे रेलवे रसीद संबंधित थी। इस मूल रूप में दस्तावेज़ की मूल सामग्री से एकमात्र निष्कर्ष यह हो सकता है कि मैसर्स शेओपर्सबाड बिमल कुमार जिसका आरोपी नंबर 3 मालिक है, ने रेलवे से माल प्राप्त करने के लिए तीसरे व्यक्ति से यह रसीद प्राप्त की। इससे आरोपी नंबर 1 द्वारा 18 फरवरी को माल की डिलीवरी लेने और उसे आरोपी नंबर 3 के खाते में राष्ट्रीय परिवहन कंपनी के पास संग्रहीत करने और गोदाम रजिस्टर में प्रविष्टियों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा।

हिम्मतलाल, पी-डब्लू- 13, गोदाम- कीपर है उन्होंने रसीद प्रदर्श पी 1 जारी की जिसमें रिकॉर्ड किया गया:

"हमें आज शिव प्रसाद बिमल कुमार की ओर से और उनके ग्रहणाधिकार के तहत हमारे गोदाम नंबर आईपीएल में भंडारण के लिए निम्नलिखित सामान प्राप्त हुआ है।"

यह इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि माल शेओपरशाद बिमल कुमार यानी आरोपी नंबर 3 की ओर से संग्रहीत किया गया था। ग्रहणाधिकार के

तहत' शब्द इस संबंध में बहुत महत्व रखते हैं और बताते हैं कि आरोपी नंबर 3 की ओर से केवल इसलिए भंडारण नहीं दिखाया गया था क्योंकि एंगल आयरन आरोपी नंबर 1 द्वारा भेजे गए थे, जो आरोपी नंबर 3 का कर्मचारी था। 'ग्रहणाधिकार के तहत' अभिव्यक्ति आरोपी नंबर 3 वस्तुओं के भंडारण के लिए परिवहन कंपनी और नेशनल के बीच कुछ निर्दिष्ट लेनदेन होने की ओर इशारा करती है। यह नोट हिम्मतलाल के बयान की पुष्टि करता है कि उसने सबसे पहले खातों में लिखा था कि माल शेओपरशाद बिमल कुमार के खाते में प्राप्त हुआ था और आरोपी नंबर 1 से प्रदर्श जेड 8 की प्राप्ति पर उन वस्तुओं के संबंध में प्रविष्टियों में उसने अकाउंट प्यारे लाल ये शब्द नोट किए थे।

यह परिस्थिति कि आरोपी नंबर 3, आरोपी नंबर 1 की तुलना में लेनदेन को वित्तपोषित करने के लिए बेहतर स्थिति में था, प्रदर्श जेड 7 की मूल सामग्री से पूर्वोक्त निष्कर्ष के अनुरूप भी है।

इस दस्तावेज़ एक्जिबिट जेड 7 में पहली पंक्ति की स्पष्ट रूप से बाद में की गई टिप्पणी के अलावा, ऐसा कोई अच्छा कारण नहीं दिखता है कि रसीद को इस रूप में क्यों लिखा जाना चाहिए था यदि इसे अभियुक्त संख्या 2 के कहने पर लिखा जाना था। प्यारे लाल का पता सी/ओ मैसर्स बताने का कोई कारण नहीं था। शेओपरशाद बिमल कुमार. इस दस्तावेज़ में बाद की प्रविष्टि, एक उद्देश्य के लिए रही होगी और वह केवल यह दिखाने

के लिए हो सकती थी कि रेलवे रसीद संख्या 43352 का निपटान आरोपी नंबर 2 द्वारा किया गया था, न कि आरोपी नंबर 3 द्वारा।

यहां उल्लेख किया जा सकता है वो यह तथ्य है कि कुछ गवाहों ने जिन्होंने अपने पुलिस बयानों के दौरान, आरोपी नंबर 3 के कुछ कार्यों का उल्लेख किया था, अदालत में कहा कि वे कार्य आरोपी नंबर 2 द्वारा किए गए थे। उन गवाहों के किसी भी बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस तथ्य का उल्लेख सिर्फ यह दिखाने के लिए किया गया है कि यह मूल रूप से यह दिखाने के लिए तैयार किए गए दस्तावेज़ को परिवर्तित करने के पहले प्रयास में फिट बैठता है कि आरोपी नंबर 3 ने इस जाली रेलवे रसीद को एक दस्तावेज़ में बदल दिया था, जिसमें दिखाया गया था कि यह आरोपी नंबर 3 नहीं बल्कि आरोपी नंबर 2 है, जिसने उस रसीद का सौदा किया।

आरोपी नंबर 2 दलाल के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने एक्जिबिट के पर हस्ताक्षर किए। उन्हें उस भाषा से परिचित होना चाहिए जिसमें उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। यह आवश्यक नहीं था कि रसीद एक्जिबिट जेड 7 अंग्रेजी या हिंदी में लिखी गई हो, भले ही आरोपी नंबर 2 उनमें से कोई भी भाषा नहीं जानता हो।

इसलिए हम दस्तावेज़ एक्जिबिट जेड 7 की रिकॉर्डिंग के संबंध में आरोपी नंबर 3 के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है, हम मानते हैं कि उन्होंने यह दस्तावेज़ लिखा था। इसमें उस जाली रसीद का जिक्र है जिसका फायदा लोहे के एंगल की डिलीवरी लेने में उठाया गया। आरोपी नंबर 3 द्वारा इस तरह की रसीद लिखना स्पष्ट रूप से आरोपी नंबर 1, उसके कर्मचारी द्वारा लोहे के एंगल की डिलीवरी लेने से संबंधित होने की ओर इशारा करता है। एक बार जब जाली रसीद का पता आरोपी नंबर 3 से लग जाता है, तो उसके अपने लेखन से, स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि उसने ही इसे रेलवे अधिकारियों से उन सामानों की डिलीवरी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने कर्मचारी आरोपी नंबर 1 को दिया था। इस प्रकार उसने आरोपी नंबर 1 को उन सामानों की डिलीवरी प्राप्त करने और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अपराध करने में सहायता की। आगे का तथ्य यह है कि रसीद दत्ता के नाम पर समर्थित थी, न कि आरोपी नंबर 1 के नाम पर, यह भी साबित होता है कि आरोपी नंबर 3 को पता होगा कि वह जिस रसीद का लेनदेन कर रहा था, वह उस माल की असली रसीद नहीं थी। की डिलीवरी लेनी थी। यदि उसे विश्वास होता कि रसीद असली है, तो उसने इसका पृष्ठांकन कर दिया होता या अपने कर्मचारी के वास्तविक नाम पर पृष्ठांकित करवा दिया होता। उनके कर्मचारी ने भी फर्जी नाम से डिलीवरी नहीं ली होगी। इसलिए हमारी राय है कि इन विभिन्न परिस्थितियों और तथ्यों से यह स्थापित होता है कि आरोपी नंबर 3 ने आरोपी नंबर 1 द्वारा आरोप नंबर 2 से 6 की विषय वस्तु, अपराध के कमीशन को बढ़ावा दिया था।

आरोपी नंबर 2 के पक्ष में बातें यह हैं कि वह अलौह धातुओं का कारोबार नहीं करता है और इसलिए उसने 17 फरवरी को पता चलने के बाद लेनदेन में कोई दिलचस्पी नहीं ली होगी कि माल लौह था और अलौह नहीं। तथ्य यह है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम के खातों में माल उसके नाम पर संग्रहीत नहीं किया गया था।

लेकिन पहली बार में नंबर 3 के नाम से संग्रहीत थे, यह भी उनके पक्ष में जाता है। यदि आरोपी नंबर 3 का इससे कोई लेना-देना नहीं था और आरोपी नंबर 1 सिर्फ आरोपी नंबर 2 के लिए काम कर रहा था, तो उसने पहली ही बार में हिम्मतलाल को निर्देश भेज दिया होता कि माल आरोपी नंबर के खाते में जमा किया जाए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने गोदाम तक लोहे के एंगल पहुंचाने वाली आखिरी लॉरी से प्यारेलाल के नाम से माल भंडारण की सूचना भेजी। प्यारेलाल का नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ कोई पिछला लेन-देन नहीं था।

इस संबंध में, आरोपी नंबर 1 द्वारा दिया गया सटीक निर्देश कुछ महत्व रखता है। एक्जिबिट जेड 8 में उनके द्वारा दिया गया निर्देश था कृपया प्यारे लाल खाते के नाम पर रसीद दें। अनुरोध यह नहीं था कि माल प्यारे लाल का था इसलिए उसके खाते में रखा जाए। वह स्वाभाविक दिशा होनी चाहिए थी। फिर रसीद प्यारे लाल के नाम पर जारी की गई होगी, किसी और के नाम पर नहीं। इसलिए आरोपी नंबर 1 द्वारा दिए गए



निर्देश से संकेत मिलता है कि कुछ उद्देश्यों के लिए वह चाहता था कि रसीद केवल प्यारे लाल के नाम पर हो। स्वाभाविक रूप से, हिम्मतलाल को गोदाम की किताबों में कुछ प्रविष्टियाँ करनी पड़ीं जो प्यारे लाल के नाम पर जारी रसीद के अनुरूप होंगी। इसलिए हिम्मतलाल ने मूल नोट "अकाउंट शीओपरशाद बिमल कुमार" के नीचे "अकाउंट प्यारे लाल" शब्द नोट कर लिया, लेकिन रसीद प्रदर्शनी पी में यह बयान देने का कोई कारण नहीं देखा कि माल प्यारे लाल की ओर से संग्रहीत किया गया था और इसमें नोट किया गया था कि वे शेओपरशाद बिमल कुमार की ओर से और ग्रहणाधिकार के तहत संग्रहीत किए गए थे।

आरोपी नंबर 2 ने डिलीवरी ऑर्डर जारी करने के लिए एक्जिबिट के, के पत्र पर हस्ताक्षर किए। उनका स्पष्टीकरण यह है कि उन्होंने ऐसा तब किया जब आरोपी नंबर 3 ने जोर देकर कहा कि उनके कर्मचारी ने गलती से उनके नाम पर सामान जमा कर लिया है। आमतौर पर, आरोपी नंबर 2 को इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं था कि आरोपी नंबर 1 गलती से सामान अपने नाम पर रख ले। उसे सीधे तौर पर किसी चीज पर संदेह हो सकता था और हो सकता है, लेकिन रसीद प्रदर्श जेड 7 दिखाए जाने से वह इस तरह के संदेह को दूर कर सकता है, जिससे पता चलता है कि माल को उस व्यक्ति की ओर से मंजूरी दे दी गई थी, जिसने रसीद पास की थी। वह आरोपी नंबर 3 के प्रति बाध्य था और यह संभव है कि वह आरोपी नंबर 3 के पत्र प्रदर्श के, पर हस्ताक्षर करने

के अनुरोध का दृढ़ता से विरोध नहीं कर सका। आरोपी नंबर 3 को प्यारे लाल द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र प्राप्त करना आवश्यक था जब माल को उसके खाते में संग्रहीत नहीं दिखाया गया है, लेकिन वह प्यारे लाल या शेओपरशाद बिन कुमार और प्यारे लाल दोनों के खाते में नहीं था।

गौरतलब है कि आरोपी नंबर 2 ने खुद माल की डिलीवरी नहीं ली थी। यह आरोप लगाया गया था कि नंबर 1 ने दो लॉट में डिलीवरी ली थी और हर बार प्यारे लाल के नाम पर रसीद पर हस्ताक्षर किए थे।

यदि आरोपी नंबर 2 भी रेलवे से बेईमानी से माल प्राप्त करने में एक पक्ष था, तो नामों के ऐसे दोहराव जिनकी ओर से माल को राष्ट्रीय परिवहन कंपनी के पास संग्रहीत किया गया था या ऐसे किसी के लिए दस्तावेज को एक्जिबिट जेड 7 प्रतिबद्धता के रूप में अस्तित्व में रखना या अभियुक्त नंबर 2 के लिए दस्तावेज को अपने पास रखने का कोई अवसर नहीं होता, उन्होंने इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखा और जांच के दौरान इसे इसी उद्देश्य से पेश किया। हो सकता है कि जब आरोपी नंबर 3 ने अपना संदेह दूर करने की कोशिश की हो। उनसे पत्र एक्जिबिट के पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया था, आरोपी नंबर ने स्वयं ही रसीद एक्जिबिट जेड 7 का पता, उसके नाम पर रखने का सुझाव दिया था, क्योंकि केवल तभी वह रसीद उसके लिए किसी मदद की हो सकती थी। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि आरोपी नंबर 1 द्वारा विभिन्न अपराधों को अंजाम देने

में आरोपी नंबर 2 की मिलीभगत बिना किसी संदेह के स्थापित नहीं होती है।

इसलिए हम प्यारे लाल की अपील को स्वीकार करते हैं और उसे उन अपराधों से मुक्त कर देते हैं जिनके लिए उसे दोषी ठहराया गया था। अभियुक्त संख्या 3, शिव प्रसाद चुन्नीलाल जैन की अपील, धारा 34 आईपीसी, सपठित धारा 109 आईपीसी, विभिन्न अपराधों के लिए उसकी सजा में बदलाव करके हम अपील को खारिज करते हैं, दोषसिद्धि को कायम रखते हैं।

अपील संख्या 185 की अनुमति दी गई, अपील संख्या 150 खारिज कर दिया गया । दोषसिद्धि को और सजा बरकरार रखी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती सोनिका पुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।